खंड . 2 अंक . 4 नवंबर 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

केंद्रीय जल आयोग CENTRAL WATER COMMISSION आपो ज्योति रसोऽमृतम्

विषय-वस्तु

- ऊपरी भद्रा परियोजना
- रिहन्द जलाशय समिति की बैठक
- उत्तर कोयल के लिए 23वीं टीईसी बैठक
- 11वीं निवेश अनुमति समिति की बैठक
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकें
- पर्यावरणीय प्रवाह मूल्यांकन पर कार्यशाला
- स्थायी समिति की बैठकें
- लघु सिंचाई की बेंचमार्किंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- ई-पीएएमएस- बाढ़ मॉड्यूल का लांच
- राजस्थान एवं सर हिंद फीडर के लिए विशेषज्ञ टीम का दौरा
- परियोजना प्रबोधन
- बाढ़ की स्थिति
- बाढ़ प्रबंधन पर कार्यशाला: जलाशय प्रबंधन
- टीएचडीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन
- डीआरआईपी / ओडिशा सरकार के साथ एमओयू
- दीर्घा - स्वछता ही सेवा
- डिजाइन परामर्श कार्य - पूर्वोत्तर का दौरा
- जलाशय प्रबोधन
- भारत का सिंचाई एटलस
- ग्लेशियल लेक प्रबोधन
- राज्यों से समाचार
- जल क्षेत्र समाचार
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह
- सेवानिवृत्ति / पदोन्नति
- शोक सन्देश

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

संदेश

जल क्षेत्र में अधिक से अधिक हितधारकों की भागीदारी के साथ अभिशासन संरचना/नीति में सुधार देखने को मिल रहा है. के.ज.आ. ने सात दशकों से भी अधिक समय से जल संसाधन विकास और प्रबंधन में देश की सराहनीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जल क्षेत्र में देश के प्रमुख संगठन का नेतृत्व करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता और जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है.

अक्टूबर 2019 के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हुईं. त्रिपुरा में सबरूम कस्बे के लिए पेयजल आपूर्ति योजना हेतु भारत द्वारा फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी लेने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन 05.10.2019 को हस्ताक्षर किए गए. सबरूम शहर को पेयजल की वर्तमान आपूर्ति अपर्याप्त है और इस क्षेत्र के भूजल में उच्च लौह तत्व है. इस योजना के कार्यान्वयन से सबरूम शहर की 7000 से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा.

निवेश अनुमति समिति की 11वीं बैठक सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 11.10.2019 को आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की दो परियोजनाएँ नामतः जिगाँव सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत रु. 7764.39 करोड़ और पूरना बैराज-2 (नेर धमाना) की रु.888.43 करोड़ की संशोधित लागत अनुमान (द्वितीय आरसीई) के निवेश की अनुमति हेतु सिफारिश की गई.

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत हीराकुंड बांध हेतु अतिरिक्त स्पिलवे के डिजाइन में सहायता करने के लिए के.ज.आ. ने ओडिशा सरकार के साथ एक एमओयू किया है. के.ज.आ. ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के साथ भूकंपीय वेधशाला स्थापित करने और टीएचडीसीआईएल को डेटा प्रदान करने तथा भूटान में प्रस्तावित संकोश बहुउद्देशीय परियोजना के अनुप्रवाह पर जल विज्ञानी प्रेक्षण स्थल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए.

के.ज.आ. ने एनआईसी के सहयोग से, जल संसाधन परियोजनाओं के कुशल और पारदर्शी मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाइन परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएएमएस) विकसित की है. इसका बाढ़ मॉड्यूल, जीएफसीसी, पटना में लॉन्च किया गया तथा 22 से 23 अक्टूबर 2019 के दौरान बिहार राज्य सरकार, जीएफसीसी और के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के लिए इसके संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

अक्टूबर माह के दौरान, 7 अतिरिक्त जलाशयों को जलाशय निगरानी नेटवर्क में शामिल किया गया. अब, के.ज.आ., देश भर के 120 जलाशयों की निगरानी करता है जिनकी कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 170.328 बीसीएम है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.06% है.

सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता वाली यमुना स्थायी समिति, को बाढ़ नियंत्रण कार्यों / किसी नए ढांचे के प्रतिकूल प्रभाव से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हितों की रक्षा तथा यमुना नदी में पर्याप्त जलमार्ग की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 16.10.2019 को आयोजित इसकी 90 वीं बैठक में, यमुना नदी पर विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मॉडल / व्यवहार्यता अध्ययन समिति द्वारा स्वीकार किए गए.

केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 'स्वछता ही सेवा' की शपथ दिलाई गई एवं डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा करवाई गई तथा उन्होंने देश भर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रमदान गतिविधियों में भाग लिया.

अक्टूबर 2019 के दौरान के.ज.आ. के दो पूर्व अध्यक्षों, श्री आर.बी. शाह और श्री एस.के. दास का निधन हो गया. के.ज.आ. द्वारा भारत के साथ-साथ पड़ोसी देश में जल क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई.

अध्यक्ष, के.ज.आ. के तौर पर मेरे कार्यकाल में 'जलांश' का यह पहला अंक है. मैं पाठकों और हितधारकों से इसमें निरंतर सुधार हेतु उनके सुझावों और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने का अनुरोध करता हूँ. इसके अलावा, जल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य समान संगठन, इस मासिक सूचना पत्र में समावेश करने के लिए अपेक्षित सामग्री / जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं.

श्री यू.पी.सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार में अपने समकक्ष के साथ 05.10.2019 को फेनी नदी के पानी के बंटवारे के लिए दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के दौरान के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में 30.10.2019 को 'ईमानदारी - एक जीवन शैली' विषय पर सतर्कता जागरूकता के लिए आयोजित सम्मेलन.

ऊपरी भद्रा परियोजना

ऊपरी भद्रा परियोजना, कर्नाटक की डीपीआर के मूल्यांकन के संबंध में एक बैठक सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 10.10.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस परियोजना में प्रस्तावित प्रमुख विशेषताओं में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई उपलब्ध करवाना तथा इस परियोजना में भूजल पुनर्भरण और पेयजल जरूरतों के लिए आवश्यक 267 लघु सिंचाई टैंक को भरने का प्रस्ताव है. संशोधित जल आवंटन, लागत पहलुओं आदि सहित परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. ने इस परियोजना के लिए परियोजना प्राधिकारियों से सभी अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए कहा और फ़ास्ट ट्रैक क्लीयरेंस का आश्वासन दिया.

उत्तर कोयल के लिए 23वीं तकनीकी मूल्यांकन समिति(टीईसी) की बैठक

परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव द्वारा 22.08.2019 को बुलाई गई समीक्षा बैठक के लिए की गई अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की 23वीं बैठक 03.10.2019 को आयोजित की गई.

टीईसी की बैठक के दौरान, राज्य सरकार के वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्थिति, झारखंड और बिहार राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, नहर की लाइनिंग के मुद्दे पर तकनीकी टीम की रिपोर्ट तथा परियोजना के बाकी कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति की स्थिति पर चर्चा की गई.

रिहंद जलाशय समिति

रिहंद जलाशय के लिए संयुक्त प्रचालन समिति (जेओसी) की 32वीं बैठक, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 18.10.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई. जेओसी में सीईए, यूपी एवं बिहार राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व शामिल है और इसका मूल उद्देश्य बिहार की जल उपलब्धता, सिंचाई आवश्यकताओं और उत्पन्न होने वाली बिजली का आकलन करने के बाद रिहंद जलाशय से इष्टतम जल छोड़ना सुनिश्चित करना है. इस बैठक के दौरान, समिति ने 2018-19 (25-सितंबर-18 से 24-सितंबर-19) के लिए प्रचालन योजना की समीक्षा की और 2019-20 हेतु प्रचालन योजना को अंतिम रूप दिया.

11वीं निवेश अनुमति समिति की बैठक

निवेश अनुमति समिति की 11वीं बैठक सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जलशक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 11.10.2019 को आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की दो परियोजनाएँ नामतः रु. 7764.39 करोड़ की अनुमानित लागत वाली जिगांव सिंचाई परियोजना और रु. 888.43 करोड़ की संशोधित लागत अनुमान (द्वितीय आरसीई) वाली पूर्णा बैराज -2 (नेर धमाना) में निवेश की अनुमति हेतु सिफारिश की गई. जिगाँव सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में तापी नदी की सहायक नदी, पूर्णा में मिट्टी के बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है. परियोजना में जलाशय की परिधि के साथ 12 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से बुलडाना और अकोला के सूखा प्रभावित जिलों में सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गई है. परियोजना में पेयजल आपूर्ति के लिए 12.95 एमसीएम और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए 21.81 एमसीएम का प्रावधान भी शामिल है. पूर्णा बैराज 2, महाराष्ट्र के अकोला जिले में पूर्णा नदी पर एक मध्यम सिंचाई परियोजना है. इससे जिले में 6954 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जानी है.

पूर्णा बैराज

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 71वीं बैठक

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 71वीं बैठक 18.10.2019 को गुवाहाटी में अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित की गई. श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. ने इसके एक सदस्य के तौर पर बैठक में भाग लिया. बैठक के दौरान निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई.

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन कार्यों की निगरानी
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सीधी भर्ती के लिए ईडीसीआईएल का सहयोग
- स्थानीय जनजातियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की जल प्रबंधन प्रथाओं के वैज्ञानिक प्रसार एवं सुधार के लिए नई पहल
- नॉर्थ ईस्ट वाटर रिसोर्सेज डेटा शेयरिंग सेंटर की स्थापना
- बाढ़ और तटबंध कटाव के नियंत्रण के लिए साफ्ट समाधानों के प्रति नया दृष्टिकोण

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की टीएसी

सदस्य(आरएम), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-बीबी) ने 9 से 11 अक्टूबर 2019 के दौरान "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप के संरक्षण" के लिए चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए, इस योजना के विभिन्न स्थानों का दौरा किया.

इस दौरे के दौरान, टीम ने निष्पादित किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और स्थल की आवश्यकता के अनुसार सुझाव/सिफारिशें कीं.

भारत के लिए पर्यावरणीय प्रवाह निर्धारण एवं कार्यान्वयन पर कार्यशाला

भारत के लिए पर्यावरणीय प्रवाह निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 21.10.2019 को दिल्ली में किया गया. नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा (एनएमसीजी) द्वारा भारत-जर्मन सहयोग की उनकी परियोजना "गंगा संरक्षण के लिए सहायता" (एसजीआर) सहित भारतीय, यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को साझा किया गया. माननीय मंत्री ने भारत में पर्यावरणीय प्रवाह निर्धारण : भारतीय और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण का सम्मिलन पर ड्राफ्ट गाइडेंस डॉक्यूमेंट का विमोचन भी किया. ड्राफ्ट गाइडेंस डॉक्यूमेंट को के.ज.आ. और यूरोपीय संघ विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है. यह प्रायोगिक नदी बेसिनों और यूरोपीय संघ से सीखे गए सबक पर आधारित है. प्राथमिकता क्षेत्र -2 (पर्यावरण प्रवाह) पर संयुक्त भारत-यूरोपीय संघ के अध्ययन का उद्देश्य मॉडल / सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं सहित देश में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए ई-प्रवाह के आकलन के लिए पद्धतियों का मानकीकरण करना है.

इस कार्यशाला में के.ज.आ. के कई अधिकारियों ने भाग लिया, पेपर प्रस्तुत किए और पैनल चर्चाओं में भाग लिया. श्री भोपाल सिंह, मुख्य अभियंता(यूजीबीओ), के.ज.आ. ने "गंगा बेसिन में पर्यावरणीय प्रवाह के कार्यान्वयन" पर एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत में ई-प्रवाह नीति और प्रावधानों, गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रवाह की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं पर विचार व्यक्त किया. के.ज.आ. द्वारा गंगा में ई-प्रवाह की निगरानी के कार्यान्वयन करते समय जो विभिन्न मुद्दे सामने आए उन पर भी चर्चा की गई. के.ज.आ., 01.01.2019 से गंगा बेसिन में ई-फ्लो की निगरानी का कार्यान्वयन कर रहा है और तिमाही आधार पर एनएमसीजी को निगरानी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है. श्री एन.एन. राय, निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण) ने भारतीय हिमालयी और उप-हिमालयी नदी घाटियों के पर्यावरणीय प्रवाह के निर्धारण अध्ययन के अनुभवों पर प्रस्तुति दी.

श्री भोपाल सिंह

श्री एन.एन. राय

कोसी उच्च स्तरीय समिति की बैठक

जीएफसीसी, अध्यक्ष की अध्यक्षता में कोसी उच्च स्तरीय स्थायी समिति (केएचएलएससी) ने 17 से 20 अक्टूबर 2019 के दौरान कोसी नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान, यूपी और बिहार के संबंधित विभागों के अधिकारी, सीडब्लूपीआरएस, पुणे और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. समिति ने 2020 के बाढ़ से पहले गंडक नदी के दाहिने किनारे पर कटाव-रोधी कार्यों की सिफारिश की. अनुशंसित कार्य, कोसी नदी के नेपाल और भारत दोनों के हिस्से में थे.

गंडक उच्च स्तरीय समिति की बैठक

जीएफसीसी, अध्यक्ष की अध्यक्षता में गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति (जीएचएलएससी) ने 23 से 25 अक्टूबर 2019 के दौरान गंडक नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान, यूपी और बिहार के संबंधित विभागों के अधिकारी, सीडब्लूपीआरएस, पुणे और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. समिति ने 2020 के बाढ़ से पहले गंडक नदी के दाहिने किनारे पर कटाव-रोधी कार्यों की सिफारिश की. अनुशंसित कार्य, गंडक नदी के नेपाल और भारत दोनों के हिस्से में थे.

यमुना स्थायी समिति की बैठक

सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में यमुना स्थायी समिति को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बाढ़ नियंत्रण कार्यों / किसी नई संरचना के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि यमुना नदी में पर्याप्त जलमार्ग उपलब्ध रहे. यमुना स्थायी समिति की 90वीं बैठक 16.10.2019 को सदस्य (आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में, चार परियोजनाओं के लिए मॉडल / व्यवहार्यता अध्ययन को स्वीकार किया गया:

- तिलक ब्रिज और आनंद विहार स्टेशन के बीच तीसरी और चौथी लाइन के लिए उत्तर रेलवे का नया यमुना ब्रिज
- वज़ीराबाद बैराज के अनुप्रवाह के तरफ चरण -4 के मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर यमुना नदी पर एमआरटीएस का पुल
- वज़ीराबाद ब्रिज व सलीमगढ़ बायपास के बीच तथा रिंग रोड बायपास (आईटीओ) व डीएनडी के बीच रिंग रोड के सामानांतर यमुना नदी के साथ एलिवेटेड रोड की व्यवहार्यता अध्ययन
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कारीडोर के लिए यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल

लघु सिंचाई योजनाओं की बेंचमार्किंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं की समस्याओं की समीक्षा और समाधान करने के लिए जल संसाधन विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा 18.10.2019 को कोहिमा में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए बेंचमार्किंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का उद्घाटन, जल संसाधन विभाग, नागालैंड सरकार के माननीय सलाहकार, श्री नामरी नचांग द्वारा किया गया. कार्यशाला में पूरे देश से प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रतिनिधियों और वक्ताओं में जल और कृषि क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल थे. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(पीओएमआईओ), के.ज.आ. ने सभा को संबोधित किया और बताया कि सरकार, नागरिकों को पेयजल सुलभ करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

ई-पीएएमएस के बाढ़ मॉड्यूल का शुभारंभ

ई-पीएएमएस के लिए बाढ़ मॉड्यूल का शुभारंभ

के.ज.आ., ने एनआईसी के सहयोग से, जल संसाधन परियोजनाओं के कुशल और पारदर्शी मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाइन परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएएमएस) विकसित की है. ई-पीएएमएस में, सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण/तटीय संरक्षण परियोजनाओं सहित वे परियोजनाएं जिनकी देखरेख गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) द्वारा की जाती है तथा बाह्य रूप से सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु प्रत्येक के लिए तीन मॉड्यूल हैं.

ई-पीएएमएस की सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के मॉड्यूल का शुभारंभ 05.09.2018 को किया गया और यह 25.02.2019 के औपचारिक शुभारंभ से प्रचालन में है तथा तब नई दिल्ली में ई-पीएएमएस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी.

इस बाढ़ मॉड्यूल को, इसके सफल परीक्षण के बाद, श्री सी.के.एल दास, सदस्य(सी), जीएफसीसी द्वारा जीएफसीसी, पटना में 22.10.2019 को श्री अतुल जैन, मुख्य अभियंता(पीएओ), के.ज.आ., श्री अतुल नायक, मुख्य अभियंता(एलजीबीओ), के.ज.आ., श्री ए.के. सिंह, इंजीनियर-इन-चीफ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और श्री सज्जाद अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी की उपस्थिति में लॉन्च किया गया. दिनांक 22 से 23 अक्टूबर 2019 के दौरान बिहार सरकार, जीएफसीसी और के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के लिए ई-पीएएमएस पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई. के.ज.आ. और एनआईसी के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को सिंचाई और बाढ़ दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए ई-पीएएमएस के माध्यम से प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन के हर पहलू से परिचित कराया.

कार्यशाला के लिए प्रशिक्षक

विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति द्वारा राजस्थान फीडर और सर हिंद फीडर का दौरा

आरडी 119700 से 447927 तक सरहिंद फीडर और पंजाब के आरडी 179000 से 496000 तक राजस्थान फीडर की रिलाईनिंग" के पूर्ण होने तक सभी दृष्टिकोणों से समग्र कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए "विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति'' का गठन किया गया है. यह के.ज.आ. के सदस्य(डब्लूपीएंडपी) के नेतृत्व में है और इसमें पंजाब व राजस्थान राज्य सरकार, सीएसआरएमएस, आईआईटी, दिल्ली आदि का प्रतिनिधित्व शामिल है. इस समिति ने 22 से 24 अक्टूबर 2019 के दौरान परियोजना का दौरा किया एवं कार्य का निरीक्षण किया तथा कार्य निष्पादन की अवधि के दौरान राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा की और उपयुक्त निर्माण के लिए सुझाव दिए.

परियोजना प्रबोधन

केंद्रीय जल आयोग, अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रगतिधीन जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी करता है. यह अड़चनों की पहचान करने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि धन का सही उपयोग किया जा रहा है तथा आगे की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधार तैयार करता है. महीने के दौरान, प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाईएआईबीपी) के अंतर्गत चल रहीं, प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए के.ज.आ. की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा दो प्रबोधन दौरे किए गए. गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान 485.37 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता में पहली किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव की सिफारिश ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय को 30.10.2019 को की गई.

के.ज.आ., पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के अलावा, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सीएडीएंडडब्ल्यूएम कार्यों एवं सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) स्कीम , बाढ़ प्रबंधन योजनाओं आदि योजनाओं की निगरानी में भी शामिल है. इस संदर्भ में, निदेशक और उप निदेशक, प्रबोधन व मूल्यांकन निदेशालय, के.ज.आ., गुवाहाटी ने असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 5 (पांच) सतही लघु सिंचाई योजनाओं नामतः ख़तडोंग फील्ड इरिगेशन स्कीम (एफआईएस), थेकेरजुली एफआईएस, डिसम एफआईएस, लाचिट एफआईएस और उदमरी एफआईएस का 24.10.2019 को दौरा किया. इन 5 योजनाओं में से 4 योजनाएं 2013-14 में स्वीकृत 60 एसएमआई योजनाओं के समूह का एक हिस्सा और उदमरी एफआईएस 15 एसएमआई योजनाओं के समूह का हिस्सा हैं. इन योजनाओं को 31.03.2020 तक पूरा किया जाना है.

असम में एक सतही लघु सिंचाई योजना

अक्टूबर 2019 के दौरान बाढ़ की स्थिति

के.ज.आ., अपने क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से हर साल बाढ़ के मौसम के दौरान वास्तविक समय के आधार पर जल वैज्ञानिक और जल - मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करता है. इस डेटा का उपयोग करते हुए, 325 स्थानों (197 स्तर और 128 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए स्तर / इनफ़्लो पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और फैक्स / ई-मेल / एसएमएस तथा वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रसारित किए जाते हैं. अक्टूबर के दौरान, कर्नाटक के बागलकोट जिले के मुधोल में घाटप्रभा नदी पर के.ज.आ.के एक स्टेशन पर 21 से 25 अक्टूबर 2019 तक चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई.

मई से अक्टूबर 2019 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में के.ज.आ. के 96 स्टेशनों पर तीव्र बाढ़ की स्थिति देखी गई.

मई से अक्टूबर 2019 के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में के.ज.आ. के 51 स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई.

अक्टूबर 2019 तक 74 जलाशयों और बांधों के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी किए गए हैं.

बाढ़ प्रबंधन : जलाशय प्रबंधन पर कार्यशाला

एनडीएमए द्वारा 18.10.2019 को ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., (जल शक्ति मंत्रालय) के सहयोग से एक राष्ट्रीय-स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जलाशय प्रबंधन और बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए अन्य रोकथाम योग्य उपायों से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया. कार्यशाला के अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :

- आईएमडी स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान में पहले से प्राप्त सुधार और अगले दो वर्षों के लिए कार्य.
- के.ज.आ. द्वारा स्थान-विशिष्ट चेतावनी और सलाह में सुधार तथा अगले दो वर्षों में कार्य की योजना.
- राज्य सरकार स्तर के मुद्दे.
- आप्लावन (इनअनडेशन) मॉडलिंग - डीईएम से जुड़े मुद्दे और इस संबंध में के.ज.आ. एवं गूगल का सहयोग.
- जलग्रहण क्षेत्रों के एकीकृत जल विभाजक विकास और प्रबंधन में चुनौतियां.
- पिछले कुछ वर्षों में जलाशय प्रबंधन के अच्छे उदाहरण.
- समग्र जलाशय प्रबंधन में रुल कर्व' और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे.

के.ज.आ. के अधिकारियों ने उपरोक्त आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रतिभागियों को बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा जलाशय प्रचालन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया.

बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी पर श्री शरद चंद्र, निदेशक (एफएफएम), के.ज.आ., द्वारा प्रस्तुति.

बाढ़ प्रबंधन के लिए जलाशय प्रचालन पर श्री ऋषि श्रीवास्तव, निदेशक(रिमोट सेंसिंग), के.ज.आ. द्वारा प्रस्तुति.

टीएचडीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन

दिनांक 25.10.2019 को ऋषिकेश में टीबीओ, के.ज.आ., कोलकाता और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल), ऋषिकेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

यह देखते हुए कि भारत सरकार के बजटीय समर्थन से संकोश बहुउद्देशीय परियोजना के लिए के.ज.आ. का भूटान और भारत में भूकंपीय स्टेशनों का एक स्थापित नेटवर्क है और टीएचडीसीआईएल को वर्ष 2016 में संकोश बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर को मंजूरी देते हुए एनसीएसडीपी द्वारा दी गई सशर्त अनुमोदन के अनुसार संकोश बेसिन में भूकंपीय अध्ययन की आवश्यकता है, दोनों संगठनों में एक सहमती बनी है जोकि, संकोश बहुउद्देशीय परियोजना पर कार्य को गति देने में उपयोगी होगा.

समझौता ज्ञापन के तहत, के.ज.आ., टीएचडीसीआईएल को भूकंपीय डेटा प्रदान करेगा और भारत व भूटान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास भूटान में प्रस्तावित संकोश बहुउद्देशीय परियोजना के अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्टेशन भी स्थापित करेगा. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र और एचओ डेटा में भूकंपीय प्रेक्षणों का डेटा न केवल टीएचडीसीआईएल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में जल संसाधन परियोजनाओं की भविष्य की योजना के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में भी उपयोगी होगा.

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

डीआरआईपी की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्री ए.के. सिन्हा, अध्यक्ष, के.ज.आ. व तकनीकी समिति की अध्यक्षता में केरल के कोझीकोड में दिनांक 24.10.2019 को बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) हेतु तकनीकी समिति (टीसी) की 24वीं बैठक आयोजित की गई.

बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (धर्मा) के संस्करण 2 के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक दिनांक 17.10.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय में आयोजित की गई. धर्मा एक वेब आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन उपकरण है जो 17 राज्यों में विकसित और संचालित है.

हीराकुड बांध का दौरा

डीआरआईपी के अंतर्गत हीराकुड बांध के लिए 9,000 क्यूमेक तक, बाढ़ के पानी के सुरक्षित निस्सरण हेतु 370 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त स्पिलवे का निर्माण किया जा रहा है. 16 से 17 अक्टूबर 2019 के दौरान गांधी हिलॉक के बाएं किनारे पर अतिरिक्त स्पिलवे के निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करने के लिए हीराकुड बांध के लिए एक तीसरे पक्ष का निर्माण पर्यवेक्षण दौरा आयोजित किया गया.

इस टीम ने ओडिशा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और हीराकुड बांध प्राधिकरणों के साथ प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों की भी समीक्षा की.

के.ज.आ. और डब्लूआरडी, ओडिशा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत हीराकुड बांध हेतु अतिरिक्त उत्प्लाव (स्पिलवे) के निर्माण से संबंधित डिजाइन और आरेखण (ड्रॉइंग) के लिए के.ज.आ. की परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. श्री सुनील नाइक, मुख्य अभियंता और बेसिन प्रबंधक, ऊपरी महानदी बेसिन, ओडिशा जल संसाधन विभाग और श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता, डिजाइन(ईएंडएनई), केंद्रीय जल आयोग ने 22.10.2019 को अध्यक्ष, के.ज.आ. तथा के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं विश्व बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया.

आईसीओएलडी - 2020

अंतर्राष्ट्रीय आयोग की 88वीं वार्षिक बैठक व बड़े बांधों पर संगोष्ठी (आईसीओएलडी), 4 से 10 अप्रैल 2020 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होना निर्धारित है. डीआरआईपी, आईसीओएलडी 2020 के आयोजन में आईसीओएलडी और आईएनसीओएलडी के साथ सहयोग कर रहा है. आईसीओएलडी 2020 के संभावित प्रायोजकों और प्रदर्शकों की एक परामर्श बैठक 30.10.2019 को सीपीएमयू कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई. बैठक में अध्यक्ष, बीबीएमबी/ अध्यक्ष आईएनसीओएलडी, सीपीएमयू, सीबीआईपी और औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

के.ज.आ., विश्व बैंक के सहयोग से संसाधन आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए बांधों के रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग के लिए एक रूपरेखा विकसित कर रहा है. 15 से 25 अक्टूबर 2019 के दौरान आगे की प्रगति के लिए, विश्व बैंक विशेषज्ञ के साथ-साथ विशेषज्ञों, अधिकारियों, कुछ बांध प्राधिकरणों की एक टीम ने उपलब्ध विभिन्न साधनों पर विचार-विमर्श किया.

श्री नित्या नंद राय, निदेशक, जल विज्ञान(दक्षिण), श्री मनीष जायसवाल, उप निदेशक, जल विज्ञान(डीएसआर) और सुश्री इस्ली इस्साक, सहायक निदेशक, जल विज्ञान(दक्षिण) ने डीआरआईपी-चरण- II के अंतर्गत 14 से 17 अक्टूबर 2019 के दौरान रायपुर, छत्तीसगढ़ में डिजाइन बाढ़ विश्लेषण पर प्रशिक्षण के दौरान व्याख्यान दिए.

दीर्घा - स्वच्छता ही सेवा

डिजाइन परामर्श - पूर्वोत्तर क्षेत्रों का दौरा

के.ज.आ. के अधिकारियों ने 14 से 17 अक्टूबर 2019 के दौरान त्रिपुरा में हौरा बांध परियोजना और चंपई चैरा बांध परियोजना तथा असम में कटाखल सिंचाई की प्रस्तावित परियोजना स्थलों का दौरा किया. टीम ने परियोजनाओं के डिजाइन के लिए आवश्यक अतिरिक्त डेटा चिन्हित किया.

सीजोस, अरुणाचल प्रदेश के स्थल का संयुक्त दौरा

के.ज.आ., मुख्यालय के डिजाइन विशेषज्ञों की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश, असम सरकार , ब्रह्मपुत्र बोर्ड और के.ज.आ., शिलांग के अधिकारियों के साथ 31.10.2019 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के सिजोस में प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा कार्यों के परियोजना क्षेत्र का दौरा किया. दौरे की शुरुआत गाँव के मुखिया और एनजीओ के साथ हुई बैठक के साथ की गई. असम- अरुणांचल प्रदेश की सीमा के पास बोरदेकोरई सिंचाई योजना के बाएं किनारे प्रतिप्रवाह (अपस्ट्रीम) पर पाकी नदी द्वारा गंभीर कटाव के कारण ग्राम प्रतिनिधियों ने अपने मुसीबतों और कष्ट को व्यक्त किया. इसके बाद, टीम ने प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा कार्य स्थल का दौरा किया और अपनी सिफारिशें की/विचार दिए.

डेकोराई सिंचाई परियोजना का दौरा

संयुक्त दल ने अरुणाचल प्रदेश और असम सीमा पर डेकोराई सिंचाई परियोजना का दौरा किया, जिसमें बैराज के प्रतिप्रवाह की तरफ कटाव प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु बैराज के गेट संचालन पर विस्तृत चर्चा की गई. असम सरकार के अधिकारियों ने जानकारी दी कि यदि कमांड से मांग की जाती है, तभी पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए फाटकों को बंद किया जाता है अन्यथा बैराज के सभी फाटकों को हमेशा ऊपर उठा कर ही रखा जाता है. इस कारण से, प्रवाह अंडर स्लूस बे अर्थात नदी के बाएँ किनारे पर अधिक केंद्रित होता है. इसलिए, नदी का बायाँ किनारा कटाव का सामना कर रहा है, जिसमें यहाँ तक कि बैराज के आउटफ्लैंक होने का खतरा है.

टीम ने सुझाव दिया कि पूरे मुद्दे पर समग्र रूप से विचार करना उचित होगा और समस्या से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है. बैराज के गेट संचालन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सुरक्षा उपाय जैसे कि रिवेटमेंट व स्पर, बैराज का संचालन, और बैराज के पूरे पहुंच की मॉडल अध्ययन की आवश्यकता पर चर्चा की गई और सुझाव दिया गया.

जलाशयों में जल संरक्षण

के.ज.आ., साप्ताहिक आधार पर देश के 113 जलाशयों की सक्रिय भण्डारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को एक साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है. अक्टूबर के दौरान, 7 अतिरिक्त जलाशयों को इस निगरानी में शामिल किया गया है.

इन 120 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 170.328 बीसीएम है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.06 % है. दिनांक 31.10.2019 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 153.299 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 90% है. इन 120 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सक्रिय भंडारण का 133% और पिछले 10 वर्ष के औसत भंडारण का 129% है.

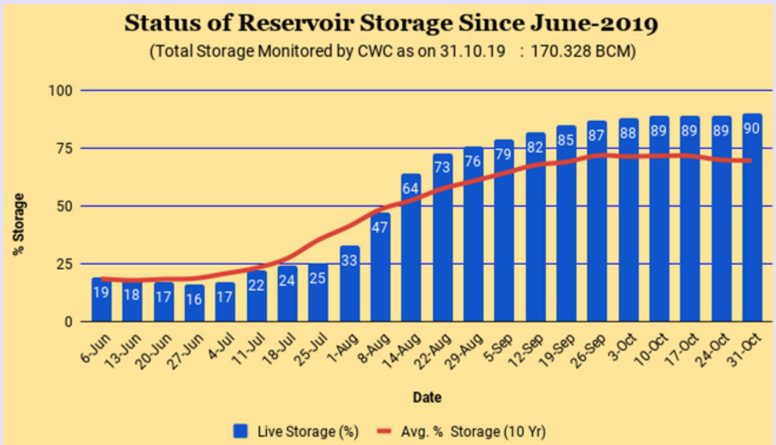

भारत का सिंचाई एटलस

भारत के सिंचाई एटलस की तैयारी के लिए अंतर-विभागीय समिति की दूसरी बैठक 18.10.2019 को श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

ग्लेशियल लेक प्रबोधन

हर साल, जून से अक्टूबर के दौरान, के.ज.आ., उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए हिमालयी क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से अधिक बड़े ग्लेशियल लेक और जल निकायों के आकार पर नज़र रखता है. इन्हें वर्ष 2009 में डिजिटाइज़ किया गया और वर्ष 2009 में आकार के संबंध में उनके वर्तमान आकारों का विश्लेषण किया गया. अगस्त 2019 के महीने में उनके आकार भिन्नता का सारांश सामने के चार्ट में दिया गया है.

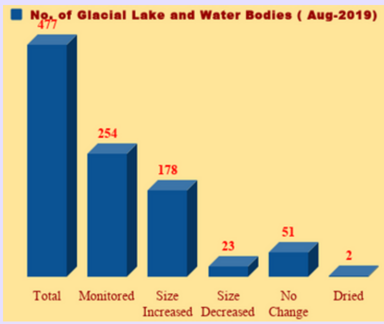

राज्यों के समाचार

अक्टूबर माह के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) से बिहार राज्य को 400 करोड़ रुपये और कर्नाटक राज्य को 1200 करोड़ रुपये की धनराशी अग्रिम रूप से दिए जाने की मंजूरी दी है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए बिहार राज्य को एसडीआरएफ की केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में रु 213.75 करोड़ की अग्रिम धनराशी की भी मंजूरी दे दी है.

जल क्षेत्र - समाचार

- इस साल **1994** के बाद हुई सबसे अधिक वर्षा (पंजाब केसरी, **01.10.2019**)
- अटल भूजल योजना जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी (नवभारत टाईम्स, **04.10.2019**)
- टिहरी बांध की बेजोड़ तकनीक के कायल हुए पूर्व पीएम देवगौड़ा (पंजाब केसरी, **07.10.2019**)
- गया, राजगीर व नवादा को मिलेगा गंगा का पानी (राष्ट्रीय सहारा, **16.10.2019**)
- **17** देशों में पेयजल समस्या गंभीर, भारत में जल महत्व समझते हैं इसलिए तालाबों की पूजा होती है : शेखावत (राजस्थान पत्रिका, **17.10.2019**)
- इंदिरा सागर बांध पर लगेगा **1,000** मेगावाट का अल्ट्रा मेगा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र (फोकस न्यूज, **18.10.2019**)
- नदियों के पर्यावरण प्रवाह का ढांचा तैयार करने में मदद करेगा जर्मनी (हिन्दुस्तान, **23.10.2019**)
- गोमुख से हरिद्वार तक अब साफ—सुथरी नजर आएगी गंगा, जल्द तैयार हो जाएंगे एसटीपी (दैनिक जागरण, **26.10.2019**)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

के.ज.आ. ने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और अधिकारियों व कर्मचारियों ने के.ज.आ., मुख्यालय में 28.10.2019 को एक शपथ ली. दिनांक 30.10.2019 को, के.ज.आ. ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2019 के दौरान, नई दिल्ली में 'ईमानदारी - एक जीवन शैली' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया. इसका उद्घाटन श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय द्वारा श्री ए.के. सिन्हा, अध्यक्ष, के.ज.आ. और मंत्रालय, के.ज.आ., एनडब्ल्यूआईसी, एनडब्ल्यूडीए, सीजीडब्ल्यूबी आदि के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया. इस कार्यशाला के दौरान श्री अरुण गौड़, पूर्व संयुक्त सचिव, यूपीएससी, श्री रविन्द्र कुमार, पूर्व निदेशक, तत्कालीन एमओडब्लूआर, श्री सुरेंद्र गर्ग, निदेशक(सतर्कता), ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय आदि ने सतर्कता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. के.ज.आ. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया. इस सप्ताह में, विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कार्यशाला, मानव श्रृंखला निर्माण, तख्तियों का प्रदर्शन, पर्चे का वितरण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गईं.

सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. सम्मेलन को संबोधित करते हुए

के.ज.आ. मुख्यालय में प्रतिज्ञा लेते अधिकारी / कर्मचारी

सेवानिवृत्ति / पदोन्नति

- श्री ए.के. सिन्हा, अध्यक्ष, के.ज.आ. 31.10.2019 को 36 साल की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए.
- श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) अधिकारी हैं उन्हें उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में पदोन्नत कर गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.

शोक सन्देश

के.ज.आ. द्वारा श्री आर.बी. शाह और श्री एस.के. दास, केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष के लिए एक श्रद्धांजलि बैठक आयोजित की गई जिनका क्रमशः 11.10.2019 और 16.10.2019 को स्वर्गवास हो गया था.

श्री आर. बी. शाह
(09.02.1932 से 11.10.2019)

श्री एस. के. दास
(07.07.1947 से 16.10.2019)

स्वर्गीय श्री आर.बी. शाह एक क्षेत्र-उन्मुख व्यक्ति थे और मुख्य अभियंता, के.ज.आ. के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारत, नेपाल और भूटान में कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और जांच के क्षेत्र में अग्रणी काम किया. उनमें से कई आज पूरे हो चुके हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं. यह सब उनके समर्पण और अथक प्रयासों के कारण है. उन्होंने अध्यक्ष, के.ज.आ. के रूप में 01.07.1989 से 28.02.1990 तक कार्य किया. वह निस्संदेह दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के व्यक्ति थे. उनकी प्रशासनिक क्षमता और इच्छा शक्ति सराहनीय थी. अधिवर्षिता के बाद भी वे बहुत सक्रिय थे और उन्होंने जल क्षेत्र में बहुत योगदान दिया. उन्हें देश में जलविद्युत विकास में उनके योगदान के लिए रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान द्वारा नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था. इस अवसर पर, उल्लेखनीय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में उनकी भूमिका को भी याद किया गया.

वर्तमान, बांग्लादेश में 1947 में पैदा हुए स्वर्गीय श्री एस.के. दास 1972 में के.ज.आ. में शामिल हुए. वे अपनी बुद्धि, योग्यता और शिक्षण कौशल के लिए जाने जाते थे. उन्होंने के.ज.आ. में डैम सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की और राज्य सरकारों को बांध सुरक्षा में पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया. उस समय, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के आयुक्त (पूर्वी नदी) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि पर दिसंबर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे. सदस्य(डीएंडआर) और अध्यक्ष, के.ज.आ. के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए. उन्होंने 01.12.2006 से 31.07.2007 तक अध्यक्ष, के.ज.आ. के रूप में कार्य किया. सेवानिवृत्ति के बाद भी, वे आईआईएम, जादवपुर विश्वविद्यालय आदि जैसे कई संस्थानों के शिक्षण कार्यों में सक्रिय रहे. वे एनडब्लूए, पुणे के नियमित विजिटिंग फैकल्टी थे.

दोनों अधिकारी, के.ज.आ. परिवार के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के प्रतीक थे. सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ वर्तमान अधिकारियों / कर्मचारियों ने इस स्मृति बैठक में भाग लिया और दिवंगत अधिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक(जल प्रणाली अभियांत्रिकी) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्दर पॉल, सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

CWC.GOV.IN /CWCOfficial.GoI /CWCOfficial.GoI /CWCOfficial_GoI c/CWCOfficialGoI